regards the number of vehicles, I have given the number of purchases made by some States in the answer.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Sir, the basic aim of our schemes is to generate employment for the educated and uneducated youths, both in urban and rural areas. We are having so many schemes like the jawahar Rozgar Yojana aad the Prime Minister's Rozgar Yojana. As far as my knowledge goes, these are all inadequate considering the magnitude of unemployment in this country. I would like to request the Minister to state whether the Government would come forward to encourage the youths, if they come in groups forming themselves into co-operatives or private limited concerns to establish industries, by providing full finance.

SHRI MANMOHAN SINGH: Sir, it is the sincere endeavour of the banking system to meet all legitimate needs for credit, provided the projects are viable. So long as the projects are a viable, bank able, proposition, I see no reason why the projects by a group of young men, whether forming co-operatives or other private entities, should be starved of resources.

गुजरात की कपड़ा मिलें

*223. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं ;

(ख) इनमें से कुल कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं और कितनी फायदे में चल रही हैं ;

(ग) क्या घाटे में चल रही मिलों को गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार इन मिलों को लाभकारी तथा अर्थक्षम बनाने और इनका आधुनिकीकरण करने के लिये क्या-क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 31-3-1994 तक की स्थिति के अनुसार गुजरात में कुल 122 सुती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के पास पंजीकृत थीं जिनमें सरकारी क्षेत्र की 28 मिलें भी शामिल हैं ।

(ख) जिन कम्पनियों ने किसी वित्तीय वर्ष के अन्तमें अपने समस्त निवल मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक की राशि के संचित घाटे उठाए हैं उनके मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को भेजे जाते हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 48 मामले बी आई एफ आर के पास पंजीकृत हैं ।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार को गुजरात राज्य वस्त्र निगम से निम्नलिखित तीन मिलों का निजीकरण करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) श्री सुभलक्ष्मी मिल्स, खामभट्ट

(2) सहयोग टैक्सटाईल मिल्स

(3) सिल्वर काटन मिल

गुजरात में किसी भी एन टी सी मिल को बेचने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) सरकार ने रुगण/बन्द पड़ी वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में पुनःस्थापना पैकेज बनाने और उसका संचालन करने के लिए बी आई एफ आर की स्थापना की है । मिलों की आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना (टी एम एफ एस) भी शुरु की गई थी ।

गुजरात में एन टी सी की मिलों के सम्बध में एन टी सी की सर्वांगीण सुधार नीति के एक भाग के रूप में उन्हें आधुनिकीकृत किया जाना है तथा अर्धक्षम बनाया जाना है ।

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Sir, the Government has evolved a rehabilitation package for the labourers. I would like to know from the hon. Minister how many labourers are given the benefit of the rehabilitation package and what the amount disbursed to them is. I would like to put another question also. An agitation, a *dharna*, is going on in Ahmedabad for the last two-and-a-half months or three months under the leadership of Shri Arvindbhai Buch and Shri Mazoor Mahajan. I would like to know from the hon. Minister why they are not given their dues according to the rehabilitation package.

MR. CHAIRMAN: Please ask the second supplementary.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Sir, part (b) of the supplementary is this. In Baroda, in Yamuna Mill, the settlement was done a few years before. Still, after so many representations by the unions and by the workers, they are not paid their dues. What is the reason for that? When will they be paid their dues?

श्री जी. वेंकटस्वामी : इस देश में 1175 टैक्सटाइल मिल्स हैं जिनमें से गुजरात में 122 टैक्सटाइल मिल्स हैं । टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड क्लॉथ एंड मैनमेड फाइबर टैक्सटाइल मिल्स 129 देश में हैं और गुजरात में 37 हैं । नंबर ऑफ मिल्स क्लोज्ड अंडर दि फाइनेंशियल लिक्विडेशन, ये 29 देश में हैं और 21 गुजरात में हैं । ऑनरेबल मैंबर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें नंबर ऑफ मिल्स ऐसिस्टेड अंडर दि टेक्सटाइल वर्कर्स रिहेबिलिटेशन स्कीम 25 देश में हैं जिसमें 19 गुजरात में हैं ।

The amount paid to the workers under the Textile Workers Rehabilitation Fund Scheme, since its inception upto 31-3-1994: India—Rs. 72.03 crores and Gujarat— Rs. 53.59 crores. The number of workers benefited under the Textile Workers Rehabilitation Fund Scheme: India—37,061 and Gujarat—27,767. The number of workers yet to receive the benefit under the TWRFS: India—11,718 and Gujarat 11,292. The provision under the TWRFS is Rs. 43.11 crores and the amount released during 1994-95 is Rs. 1 crore.

The amount sanctioned under the TMFS is Rs. 877.94 crores and for Gujarat it is Rs. 169.23 crores.

दूसरा सवाल जो उन्होंने किया है । कि मजदूर-महाजन के नेता जो हंगर स्ट्राइक या जो भी ऐक्टिविटीज : वहां पर कर रहे है तो उनके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा है अध्यक्ष जी ।

As per the letter of the State Chief Minister to the hon. Prime Minister, dated 4.6.1994, the details are as under:

Proposal for Gujarat State Textile Corporation Limited—the amount required is Rs. 96.82 crores. The member of workers involved is 15,000. The proposal was submitted on 9.1.1993. It is submitted as per the instructions of the Ministry of Industry. There is one more proposal. This Gujarat State Textile Corporation proposal was forwarded by the Chief Minister to the Prime Minister.

There is another proposal from the private sector—the proposal for the Government of Gujarat for closed textile mills. The amount required is Rs. 168.37 crores. The number of workers involved is 33,150. 19 mills are private mills; proposals submitted on 28.4.93 to help the workers of the mills under liquidation in getting their legal dues and for release of assets for economic regeneration. The details of the NRF assistance sought is given below: Legal dues to retrenched workers—Rs. 103.19 crores, funds for retraining and redeployment—Rs. 5.71 crores and funds for

employment generation activities—Rs. 59.57 crores.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: One question remained to be answered and that was with regard to the Yamuna Mills where the settlement had already been made but the dues were yet to be paid.

MR. CHAIRMAN: You put your second supplementary also. I will ask the Minister to answer them together.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: My second supplementary is this. According to the package of the Government, the labourers who are affected will be given training for undertaking new employment. They will be given the facilities. I would like to know when this package will be implemented, that is, the date from which it will become effective.

श्री जी. वेंकटस्वामी : गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो प्रोपोजल्स आए हुए हैं, गवर्नमेंट आफ गुजरात के, वह तब होंगे, जब रीहैब्लीटेशन स्कीम स्टार्ट होगी ।

MR. CHAIRMAN: There was something left out of the first question.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Perhaps, he needs a separate notice.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Why a separate notice? (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: The Minister is ready with the answer.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Sir, the workers of these mills have so far been paid Rs. 2.18 crores. One thousand four hundred and nineteen workers have been given assistance under the TWRFS.

श्री राजू भाई ए० परमार : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात में कई मिलें हैं जिनके पास सरप्लस लैंड है । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सरप्लस लैंड को बेचने के लिए गुजरात सरकार की कोई प्रोपोजल आपके पास आयी है कि नहीं । यदि आयी है तो इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं और यह सरप्लस लैंड जो है, वह बहुत ही प्राइम लैंड है । वर्कर्स के इंटरस्ट में यदि कोई प्रोपोजल गुजरात सरकार ने नहीं भेजा है तो क्या इस सरप्लस लैंड का, प्राइम लैंड का, वर्कर्स के हित में कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हैं ।

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी मैंने बताया कि गुजरात गवर्नमेंट ने दो प्रोपोजल्स भेजे हैं, वह इंडस्ट्री मिनिस्ट्री डील कर रही है, शायद कैबिनेट को जाएगा वहां से अगर आया तो जो भी मोइना। शन स्कीम है, गुजरात गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर ने मुझ से भी कहा कि अगर कैबिनेट की तरफ से 168 करोड़ और 96 करोड़ मिल जाएंगे तो हम इस प्रोपर्टी को बेच देंगे और गवर्नमेंट आफ इंडिया को वापिस करने का भी विचार है और आफ्टर माडर्नाइजेशन फैक्ट्रीज चालू करने की नई स्कीम शुरू करने को कहा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से ।

श्री राजू भाई ए० परमार : वर्कर्स के हिता की बात है । गुजरात में 50 हजार वर्कर्स, टेक्सटाइस वर्कर्स अभी बेकार हैं तो आपको मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्री को भी कह करके मंगाना चाहिए क्योंकि गुजरात में आन्दोलन चल रहा है । इसके बारे में आप थोड़ा कीन इंटरस्ट लेकर जो भी प्रोपोजल गुजरात सरकार ने भेजा है, आपको थोड़ा इंटरस्ट लेकर उसको मंगवाना चाहिए क्योंकि वहां पर 50 हजार टैक्सटाइल वर्कर्स का सवाल है ।

श्री जी. वेंकटस्वामी : मैंने रात दिन इस बात की कोशिश की है । एक जमाने में गुजरात मैनचेस्टर आफ इंडिया था, आज वहां पर बहुत सारी मिलें बंद हो गयी हैं, इसकी चिंता टैक्सटाइल मिनिस्ट्री को है । मैं आनरेबल मैंबर को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इनके जो भी इश्यू हैं और चीफ मिनिस्टर से बात की, डिटेल में प्रोग्राम मैंने डिस्कस किया है । जैसे ही कैबिनेट फैसला होगा, मैं जरूर इस के ऊपर टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से आगे

बढ़ने की कोशिश करूंगा, यह आश्वासन मैं आप को देना चाहता हूं ।

मौलाना हबीबूर रहमान नोमानी: : मैं माननीय वजीर साहब से यह जानना चाहता हूं कि ये बंद मिलें या बीमार मिलें जो हैं इन को चालू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है और उन पैसों को किस मद से खर्च किया जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो लेवी वसूल की जाती है हथकरघा चलाने वाले बुनकरों के लिए, उसी में से यह पैसा आप खर्च करते हैं ? इन मिलों का माडर्नाइजेशन करने के लिए या उन को चालू रखने के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री जी. वेंकट स्वामी: सभापति जी, आनरेबल मैंबर ने जो सवाल किया कि देश के अंदर कितनी मिलें हैं, जो बीमार हैं, कितनों का माडर्नाइजेशन करने वाले हैं, यह आनरेबल मैंबर का सवाल था । मैं उन को बताना चाहता हूं कि अभी तक टैक्सटाइल मिल्स जो बीमार हैं, जो सिक हैं वह बी०आई०एफ०आर० में 262 मिलें है । इन के माडर्नाइजेशन का कोई शोग्राम नहीं बना मगर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 750 करोड़ रुपया आई० डी० बी० आई० में रखा था । बहुत सारी मिलों ने वह पैसा लेकर अपना माडर्नाइजेशन किया है । मैं आनरेबल मैंबर को इंफार्मेशन देना चाहता हूं कि जो 122 मिलें हैं एन०टी० सी० की उनको ट्रायपार्टाइट कमेटी में एग्री किया हैं माडर्नाइजेशन के लिए । वह भी प्लान कैबिनेट के सामने जा चुका है । वह अगर आया तो सही मायने में एन० टी०सी० की तरफ से माडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरु होगा । प्राइवेट सेक्टर के लिए किस तरह से माडर्नाइज़ेशन करेंगे, यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री आफ टैक्सटाइल के सामने है,ज वह इस बार में सोच रही है ।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, the Government have set up the BIFR to evolve and manage rehabilitation packages in respect of sick mills. The hon. Minister knows the plight of the people. What is the amount that has been made available to the textile mills for their rehabilitation?

If the amount is not sufficient, I would like to know whether the hon. Minister has approached the Finance Ministry to get sufficient funds for rehabilitation of sick units, particularly in Gujarat.

श्री जी. वेंकटस्वामी : मैं माननरेबल मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि मैंने पहले ही फिगर्स दी है कि कितनी देश के अंदर मिलें सिक हैं, और गुजरात में कितनी हैं और इन के माडर्नाइजेशन के प्रोग्राम के लिए कितना पैसा दिया है । यह मैंने डिटेल में आप को सुनाया है । मगर मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हुं कि हम ने माडर्नाइजेशन की स्कीम 122 एन० टी०सी० की मिलों से शुरु करने का प्रोग्राम बनाया है और मैंने जैसे पहले कहा....

श्री सीताराम केसरी : हिन्दी में बाताया अंग्रेजी में कहते तो समझते ।..... (व्यवधान)

श्री जी. वेंकटस्वामी : ट्रासलेशन है, वह जानते भी हैं हिन्दी । माननरेबल मैंबर जानते हैं हिन्दी ।...

तो सभापति जी, मैंने कहा कि प्राइवेट टैक्सटाइल मिलों के माडर्नाइजेशन का प्रोग्राम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सोच रही है और वह प्रोग्राम सोचकर हम आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएंगे । उस प्रोग्राम को डिस्कस करने के बाद कैबिनेट में ले जाएंगे ।

श्री राधाकिशन मालवीय : माननीय सभापति जी, गुजरात में मिलें बंद पड़ी हुई हैं । हजारों लाखों मजदूर बेकार हैं । उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का भी यही हाल है । जितनी टैक्सटाइल मिलें एन० टी०सी० की हैं वह सब बंद पड़ी हुई हैं । सरकार उन मजदूरों को हजारों लाखों रुपए सैलरी दे रही है । मेरा सरकार से पूछना यह है कि जो हमारे देश में मोटे

कपड़े की बहुत जरूरत है, जैसे बैडशीट है, चादर है, मोटा कपड़ा जैसे तकिये के खोल भी है। और उसमें मार्डन टैक्नालाजी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मगर उसकी डिमांड हमारे देश में बहुत है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मजदूरों को रोजगार देने के लिये जितनी ये सिक यूनिट्स पूरे देश में टैक्सटाइल की पड़ी हैं, तो क्या यहां मोटा कपड़ा बनाने के लिये सरकार कोई व्यवस्था कर सकती है ताकि जो हजारों लाखों रुपये प्रति महीना सरकार मजदूरों को देती है कम से कम इसका तो उत्पादन करें? इस बारे में सरकार का क्या विचार है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी, आनरेबल मेंबर ने मध्य प्रदेश के बारे में कहा। मध्य प्रदेश में पटिक्युलरली इन्दौर में, वहां के आनरेबल मेंबर आज वाक-आउट किये हुए हैं, मोरारका साहब---सबसे बड़ी मिल लगी हुई है और उसके लिये हमने .....

श्री राधाकिशन मालवीय : जिस मिल को मोरारका साहब ने लिया उस मिल को सरकार ने अवार्ड दिया था। लेकिन जब वह मिल प्रोफिट में चली तो मोरारका जी ने उसको सिक यूनिट कर दिया और वहां के सब मजदूर बेकार हो गये। 6 महीने पहले जिस मिल को सरकार ने अवार्ड दिया था और जिस मिल के कपड़े की मांग फारेन में थी, वह मिल प्राइवेट हाथों में दे दी और वह मिल बन्द हो गयी और वहां के सारे मजदूर बेकार पड़े हुए हैं।

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी, इसमें सरकार का क्या दोष है, क्या कसूर है। जिसको अच्छी मिल समझा सरकार ने उसको अवार्ड दिया। अगर उसको खरीदकर मोरारका साहब ने उसको बन्द कर दिया तो उसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है, बताइये... (**व्यवधान**) सभापति जी, प्राइवेट मिल्स के जितने भी वरकर्स हैं उनके रीहैवलीटेशन स्कीम के बारे में रात दिन टैक्सटाइल मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है। बाद बीवजी पब्लिक सैक्टर प्राइवेट मिल्स के वरकर्स के लिये रीहैवलीटेशन का काम शुरू हुआ है और बहुत जगह यह आगे बढ़ा है। कुछ जगह बाकी है, उसके लिये हम कोशिश करेंगे।

श्री राधाकिशन मालवीय : मोटा कपड़ा, जिसकी डिमांड है, जिसकी आवश्यकता है यह मैंने पूछा है। इससे मजदूरों को रोजगार भी मिल जायेगा और देश में जो उसकी जरूरत है, उसकी भी पूर्ति हो जायेगी।

श्री जी. वेंकटस्वामी : इसके लिये दो ही तरीके हैं। एक तो इसको हैंडलूम में बना सकते हैं और दूसरा पावर लूम में बना सकते हैं। पावर-लूम की स्कीम लेकर अगर कोई कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से आवे, तो टैक्सटाइल मिनिस्ट्री उसकी मदद करेगी। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट आगे बढ़कर अगर कोई स्कीम ले, तो टैक्सटाइल मिनिस्ट्री उनको पूरी तरह से मदद करने के लिये तैयार है।

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : कभी-कभी ऐसा होता है कि घाटे वाली मिल प्राइवेट सैक्टर में खरीद ली जाती है और सरकार का जो पैसा है, जो लाभ हैं वह उसको तो ले लेते हैं लेकिन उन पर कुछ भी इनवैस्ट नहीं करते और फिर सिक बना देते हैं। तो इसके बारे में कुछ सोचा है?

श्री जी. वेंकटस्वामी : सरकार ले लेती है?

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : घाटे वाली मिल को प्राइवेट सैक्टर को सरकार ने दे दिया। तो उसके मार्डनाइजेशन के लिये सरकार जो देती है, वह ले लेते हैं और उस पर इनवैस्ट नहीं करते और वह मिल फिर से सिक हो जाती है और सारे मजदूर अन-इम्पलाइजईड हो जाते हैं। प्राइवेट मिल जो हैं, वे खुद इन मजदूरों को

कोई मदद नहीं कर रही है। तो मैं.....

श्री जी. वेंकट स्वामी : सभापति जी, यह क्वेश्चन है कि प्राइवेट मिल के जो मालिक हैं वे सरकार से लेते हैं और खा जाते हैं।

श्री जगत देसाई : और खोखा बना देते हैं।.....(**व्यवधान**)...

श्री जी. वेंकट स्वामी : आनरेबल मेंबर का जो क्वेश्चन है, इस मामले में हम भी बड़े चिंतित हैं। गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से ऐसे कई कानूनों की जरूरत है जिससे फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन से जो लोन लेकर ये लोग इण्डस्ट्री पर लगाने के बहाना बनाकर लेते है और नहीं लगाते और मिल को सिक कर देते हैं तो इसके लिये हम फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंशियल इन्टीट्यूशंस को इसके ऊपर ऐक्शन लेने के लिये लिखेंगे।

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Sir, the representatives from the workers' unions under the chairmanship of the hon. Minister for Textiles adopted a resolution that all the mills under the NTC shall be modernised at a cost of Rs. 2005 crores. I would like to know whether that resolution has been accepted by the Cabinet. Secondly, Sir, how many workers were retrenched with the assistance of the National Renewal Fund and what alternative employment has been provided to them and how much has the Government spent from the Rehabilitation Fund for rehabilitation of the textile workers will similar assistance be given to other workers in the textile industry including handloom industry to provide relief because under the liberalised and deregulation policy many of the handloom workers have been unemployed?

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी, सेकिण्ड क्वेश्चन के लिये मुझे सैपरेट क्वेश्चन चाहिये। और जहां तक फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल है जो एन.टी.सी. के बारे में है...(**व्यवधान**)

SHRI PRAGADA KOTAIAH: You have adopted a pious resolution. Has that resolution been adopted by the Cabinet, and if so, when you are going to take up rehabilitation and modernisation of NTC mills under the National Renewal Fund? Why could it not be spent for the rehabilitation of handloom weavers who have been unemployed on account of faulty liberalisation and deregulation policy?

श्री जी. वेंकटस्वामी : एम.टी.सी मिलें 122 हैं जिसमें 79 सिक मिलें हैं जिनके माडर्नाइजेशन का प्लान बन चुका है। यह जो टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है– सिटरा, बिटरा, निटरा के प्रोपोजल पर ट्राइपर्टाइट कमेटी आल आवर इंडिया के ट्रेड यूनियन के लीडरों की बैठाई है और उसको सेंक्शन दिया है इसमें 15 टेकओवर मिले हैं जिनको नेशनलाइज करने की जरूरत है। लीगल डिपार्टमेंट से सेंक्शन हो कर आ चुका है। केबीनेट में नोट बनकर जा रहा है। केबीनेट से जब सेंकशन होगा तो माडर्नाइजेशन का काम शुरू होगा। दो हजार पांच करोड़ का टोटल एन टी सी मिलों के माडर्नाइजेशन का है।

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Why have you adopted a discriminatory policy with regard to the unemployed people when you are providing relief to the workers of the textile mills? Why not similar relief be extended to the handloom weavers who have been unemployed? Why this discriminatory policy? You may tell us.

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति, जी यह अपने क्वेश्चन का जवाब देने का मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं। उनके क्वेश्चन का मैं पूरा जवाब दे दूं और उसके बाद सप्लीमेंटरी पूछेंगे तो उसका जवाब देने को तैयार हूं। इन्होंने पूछा है

कि कितने वर्कर्स रिट्रेंच हुए हैं। रिट्रेंच कोई नहीं हुआ है। वी आर एस के तहत 36 हजार एन टी सी मिलों के वर्कर्स गए हैं। इन्होंने कहा है कि केबिनेट में सेंक्शन आ गई है तो अभी तक केबीनेट में नहीं आई है। जैसे ही केबीनेट में आ जायेगी, मंजूरी आ जाये तो हम यह माडर्नाइजेशन का प्रोग्राम जारी रखेंगे। इन्होंने एन टी सी. मिल वर्कर्स और हैंडलूम वर्कर्स का बताया कि वहां पर इसे अमल नहीं कर रहे हैं तो मैं जरा इन्हीं से पूछना चाहता हूं...

SHRI JAGESH DESAI: Don't ask the Member.

श्री जी. वेंकटस्वामी : मैं इनसे जानना चाहता हूं कि हैंडलूम वर्कर्स को कहां निकाला? कौन सी इंडस्ट्री से हैंडलूम वर्कर्स को निकाला मेरी इन्फरमेशन के लिए बता दें तो मैं इनको सेटिसफैक्टरी रिप्लाई दे दूंगा। हैंडलूम वर्कर्स को एक एम्पलायर के द्वारा निकाला गया है तो उनके रिहेबिलिटेशन का सवाल पैदा होता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर इस देश के अंदर हैंडलूम वर्कर्स के लिए काफी काम कर रहे हैं यह अच्छी तरह से जानते हैं।

*224. [The questioners (Shri Nilotpal Basu and Shri Dipankar Mukherjee) were absent. For Answer vide Col. ...infra.]

Membership of Stock Exchanges for Foreign Financial Institutions

*225. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to permit the foreign financial institutions to become members/brokers of the Stock Exchanges; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Government do not have any proposal to permit Foreign Financial Istitutions to become members of Stock Exchanges in India. However, foreign brokers registered with SEBI are permitted to operate in India on behalf of registered foreign institutional investors. Such foreign brokers are only permitted to transmit orders to members of Indian stock exchanges. The orders shall, however, be executed on the Indian stock exchanges and contract notes issued only by members of the stock exchanges.

MR. CHAIRMAN: You put your first supplimentary please.

SHRI S. MADHAVAN: Sir, there is a fear about foreigners involving themselves in speculative share market. The hon'ble Prime Minister announced that the Government is inviting foreign investment only in infrastructural facility sector and also foreign technology. I would like to know whether it is true that foreigners are cornering the shares of the Indian companies and whether the idustrialists of India have expressed any fear on this issue. What are the reasons for allowing foreigners in speculative share market?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, we have deliberately considered it prudent to allow foreign institutional investors to operate in the Indian stock exchange markets. And in doing so, we have taken adequate care to see that these foreign institutional investors will not be able to corner a disproportionate amount of shares of any single company. There have been limits laid down for their total holdings in a company and in individual companies. There is no danger that the presence of the foreign institutional investors will necessarily lead to any take-over of Indian companies.

SHRI S. MADHAVAN: Sir, I want to know whether the Government it aware that a leading economist of this country has warned the Government that one foreign financial institution alone has got a capacity to corner the entire shares of all the Indian companies. I want to know whether it is true. If it is true, what are the precautions the Government has taken to prevent such things happening in India?

SHRI MANMOHAN SINGH: Sir, I have already mentioned that there are defined limits up to which any foreign